# मध्यप्रदेश में कृषि की स्थिति एवं कृषक आन्दोलन -राजनीतिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व

ज्योति कौरव

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल, म .प्र.

### सारांश

हमारे लोकतंत्र की नींव ही जन अंदोलन के बीच बनती है। 19 वीं और 20 वीं शताब्दी के शुरूआत में देश में अनेक किसान आंदोलन हुये और आज भी अपनी माँगों को लेकर बढ़ते ही जा रहें है। इसमें निम्न वर्ग के साथ-साथ मध्यम वर्ग व उच्च वर्ग के लोगों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया और आंदोलन द्वारा अपने अधिकारों और लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित शोधपत्र के विषय म. प्र. में कृषि की स्थिति एवं किसान आंदोलन-कृषि हेतु राजनीतिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व के माध्यम से इन्ही परिस्थितियों और आंदोलन के औचित्य-अनौचित्यता के साथ-साथ आंदोलन के राजनीतिकरण पर बल दिया जायेगा।

सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि किसान आंदोलन नया है। और कुछ असामाजिक तत्वों की उपज मात्र है वे मानते है कि यह मुद्दीभर पढ़े लिखे बदमाशों का पेशा मात्र है। भोले भाले किसानो को बहलाकर थोड़े से सफेद पोश अपना उल्लू सीधा करने पर तुले बैठे है। इसलिए यह किसान सभाओ एवं किसान आंदोलन का तुफान-ऐ-बदतमीजी बरपा रहे है। यहा इनकी हरकते जारी है यह भी नहीं कि केवल उनके पृष्ठपोषक ऐसी बातें करते है सभी दलों के शीर्ष नेता भी यह मानते है, उन्हें किसान सभा की जरूरत ही महसूस नहीं होती वे किसान आंदोलन का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मे रोड़ा समझते है फलतः इनका विरोध भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करते है।

परंतु ऐसी धारणा भ्रान्त निर्मूल है, भारतीय किसानों का आंदोलन प्राचीन है, बहुत पुराना है दरअसल इस आंदोलन के बारे में लिपिबद्ध वर्णन का अभाव एक बड़ी त्रुटी है। यदि यह कहा जाये तो सत्य प्रतीत होता है कि हमारे लोकतंत्र की नीव ही जन आंदोलन के बीच ही पनपी है। 19वी और 20वी सदी के आरंभ में भारत में अनेक किसान आंदोलन हुये और आज भी अपनी अपनी माँगो को लेकर बढ़ते ही जा रहे है जिससे निम्न वर्ग के साथ-साथ मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग ने भी बढ़चढ़कर भाग लिया और आंदोलन द्वारा अपने अधिकारो और लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रस्तावित शोध इसी प्रकृति का है। मध्यप्रदेश में हुये हाल ही में ये किसान आंदोलन जिसने पूरे राज्य में आपात जैसी स्थिति पैदा कर दी। इस आंदोलन के बीच ऐतिहासिक रहे है। सरकार सत्ता में आने से पहले किसानो

की कर्जमुक्ति आत्याधुनिक कृषि साधन और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने जैसे वादे कर किसानों के एक बंडे वोट बैंक को लुभाने का प्रयत्न किया।

मध्यप्रदेश में किसान आंदोलनों में मंदसौर का किसान आंदोलन काफि हिंसक रूप ले चुका था फायरिंग और पथराव के दौरान 6 किसानों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (म.प्र.) ने किसानों से बातचीत कर उनकी मांगों को मानने की बात की।

मेरे द्वारा प्रस्तावित शोध पत्र के माध्यम से किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन किसानों द्वारा अपनी माँगों मुख्यतया कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, किसानों पर लगे मुकदमें वापस ले, जैसी घटनओं का औचित्यपूर्ण अध्ययन किया जायेगा। मेरे द्वारा प्रस्तावित शोध का निष्कर्ष पूर्ण बिंदू कृषि और किसान रहेगा।

## म.प्र. कृषि की स्थिति

म. प्र. के लिये कृषि वास्तितक अर्थों में जीवन रेखा रही है। म.प्र. एक कृषि प्रधान राज्य है यहाँ 3/4 जनसंख्या कृषि और कृषि ये जुड़े व्यवसाय के जिरये जीवनयापन करती है और यही व्यवसायिक एकरूपता समाज को वास्तव में एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। परन्तु आज की वर्तमान स्थिति में उपरोक्त पंक्तियाँ राज्य के वास्तिवक रूप को पेश नहीं करती है। अब कृषि जीवनयापन की सहज संस्कृति नहीं बल्कि एक चुनौतीपूर्ण जाखिम भरा काम बन चुका है। नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन डाटा में किसानों की ऋणग्रस्तता पर किया गया अध्यायन यह बताता है कि म.प्र. के कुल 64 लाख किसानों में से 32 लाख किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुये है। बैंक की प्रक्रिया के कारण उनका सरकारी वित्तीय संस्थानों से विश्वास कम हुआ है। अब भी 40 प्रतिशत कर्ज ग़ैर सरकारी स्त्रोंतों से किसानों को प्रदेश में मिलता है।

अतीत की बात करना एक चुनौतीपूर्ण स्वर्णयुग की चर्चा करने जैसा है। वर्तमान यह बताता है, कि म.प्र. मे भी चूंकि सरकार ने आर्थिक उदारवाद की नीतियों को नीतिगत रूप से स्वीकार कर लिया है। इसलिये कृषि को भी अब संवेदनशील नजिरयें से देखा जाने के बजाये खुले बाजार के एक पक्ष के रूप् में ही देखा जायेगा वर्तमान में स्थिति यह है, कि कृषि पर निर्भरता तो कम नहीं हुई बल्कि उसका सामाजिक अर्थव्यवस्था में योगदान जरूर कम होता गया।

म.प्र. में किसान आंदोलन में किसानों की माँगें कुछ इस प्रकार रहीं है - कर्जमाफी, दूध के रेट, बढ़ाये फसल के खर्च का डेढ़ गुना दाम मिले, किसानों पर दर्ज केस वापस हो। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू हो।

म. प्र. के मालवा निमाड में हिंसक आंदोलन, मंदसौर की पिपलियामंडी के पास पुलिस पर पत्थर फेंके वाहन जलाये ,रेल्वे क्रासिंग का फाटक तोड़ा, पटिरयाँ उखड़ने की कोशिश की ,इस तरह का आंदोलन 1998 के बाद हुआ।

### स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें।

- िकसी फसल के प्रोडक्शन पर जितना खर्च आ रहा है। सरकार उससे डेढ़ गुना ज्यादा दाम
  दिलाये।
- सरप्लस और बेकार जमीनों को बांटा जाये।
- कृषि भूमि और जंगलों को नान-एग्रीकल्चर यूज के लिये कारपोरेट सेक्टर्स को देने पर रोक लगे।
- जंगलों में आदिवासियों और चरवाहों के जाने की इजाजत हो साथ ही कॉमन रिसोर्स पर जाने की इजाजत मिले,
- नेशनल लैंड यूज एडवायजरी सर्विस का गठन किया जाय ताकि लैंड यूज का फैसला पर्यावरण मौसम और मार्केटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हो।
- कृषि भूमि की बिक्री को रेगुलर करने के लिये मैकेनिज्म बनाया जाये, जिसमें जमीन प्रपोजल और खरीदार की कैटेगरी को ध्यान में रखा जाये।

### मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन

कृषक आन्दोलन का इतिहास बहुत पुराना है। और विश्व के सभी भागों में अलग-अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिये आन्दोलन किये है तािक उनकी दशा सुधर सके। मौजूदा दौर में भारत में कृषक आंदोलन तेज गित से बढ़ रहे है। इसका मुख्य कारण कृषक की आर्थिक हालत दिन प्रति दिन कमजोर हो रही है। और वो कर्ज के मकड़ जाल में फंस रहा क्योंकी मौजूदा दौर में कृषि में लागत बढ़ रही है। आमदनी घट रहीं है जिस कारण से किसानों में आत्म हत्या की घटनाएँ बढ़ रहीं है। दूसरी तरफ लोग कृषि नीित बदलवाने के लिए संघर्ष कर रहे है। वर्ष 2017 में देश में छोटे बड़े सैकड़ो आंदोलन देश में हुए है। सरकार को कृषि के सम्बन्ध में बोलने पर मजबूर किया है जिसमें महाराष्ट्र का जून 17 मेंगाँव बन्द हो, चाहे नासिक से मुम्बई तक का मार्च हो, राजस्थान में पानी व बिजली के सवालों पर आंदोलन ,हिरयाणा में 2015 में मुआबजे की मांग का आंदालन हो, तिमलनाडू के किसानों का महिनों तक संसद मार्ग पर धरना, जून 2018 मंदसौर किसान आंदोलन आदि मुख्यतया रहें है।

किसान आंदोलन एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। पिछले समय में देश भर में किसानों की नई ऊर्जा उभरी है। नया नेतृत्व सामने आया है। नया संकल्प जुड़ा है। लेकिन उससे भी बड़ी घटना किसान आंदोलन का बदलता स्वरूप् है। किसान की परिभाषा बदल रहीं है। किसान नेतृत्व की पृष्ठभूमि बदल रहीं है। किसान आंदोलन के मुद्दे बदल रहे है। और वैचारिक सरोकार भी बदल रहे है। आज यह बदलाव बारीक महसूस हो सकता है। लेकिन किसान आंदोलन के चरित्र में यह बदलाव किसानों की दशा और दिशा बदल सकता है।

आज का किसान आंदोलन आजादी के पहले और अस्सी के दशक के आंदोलनों से बहुत अलग है। अंग्रेजीराज के दौरान हुए किसान विद्रोह मूलतः औपनिवेशिक राज द्वारा स्थापित शोषक कृषि व्यवस्था के विरूद्ध थे | मोपला विद्रोह, चम्पारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और तेभागा आंदोलन जैसे किसान आंदोलनों ने कृषि व्यवस्था के सबसे शोषित वर्ग के न्यूनतम अधिकार की आवाज उठाई । अन्यायपूर्ण लगान , नील की बंधुआ किसानी और बटाईदार को फसल का कम से कम एक लिहाई हिस्सा देने की मांग पर चल रहे आंदोलनों ने किसान को एक राजनैतिक पहचान दी आज़ादी के बाद पहले चालीस साल तक किसानों ने स्वराज में न्याय मिलने का इंतजार किया। उसके बाद कर्नाटक में ननजुन्दमस्वामी, महाराष्ट्रा में शरद जोशी और उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकौत के नेतृत्व में किसान आंदोलनों का एक नया दौर शुरू न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी आंदोलन का नेतृत्व वह वर्ग कर रहे थे जिसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिला लेकिन जो किसान होने के नाते आर्थिक समृद्धि से वंचित थे।

इक्कीसवीं सदी के किसान आंदोलनों में किसान की नई परिभाषा का विस्तार हो रहा है। इस नई परिभाषा में किसान का मतलब सिर्फ बड़ा भूस्वामी नहीं बल्कि मंझौला और छोटा किसान भी है। ठेके पर किसानी करने वाला बटाईदार और खेतिहर मजदूर भी है। जमीन जोतने वाले के साथ पशुपालन, मुर्गीपालन और मछली पालन करने वाले को भी किसान के दायरे के भीतर शामिल किया जा रहा है।

पहली बार किसान आंदोलन आदिवासी और दिलत को किसान की तरह स्वीकार करने को तैयार है। खेती में दो तिहाई मेहनत करने वाली औरतों को अब तक किसान की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इस नए आन्दोलन में उनकी भूमिका को स्वीकार करने का मन बन रहा है। किसान की परिभाषा का यह विस्तार जरूरी था। जैसे-जैसे किसानी सिकुइ रही है। वैसे-वैसे किसानी के किसी एक हिस्से को लेकर आंदोलन चलाना असम्भव होता जा रहा है। हर तरह के किसान को जोड़कर ही नया किसान आंदोलन ऊर्जा प्राप्त कर सकता है।

नए युग के इस नए किसान आंदोलन के वैचारिक सरोकार और मुद्दे भी पुनःपरिभाषित हो रहे है। आजादी के बाद के किसान आंदोलन द्वैतवादी थे एक तरफ भारत बनाम इंडिया का मुहावरा था तो दूसरी तरफ जमीदार बनाम खेतिहर मजदूर का द्वंद्व था। नया किसान आंदोलन अद्वैतवादी है। किसानी के भीतर ऊंच-नीच का वर्ग संघर्ष जगाने की बजाय सभी किसानों को जोड़ने का आग्रह इस दौर की विशेषता है। साथ ही किसान बनाम गैर किसान की लड़ाई से बचने की समझ भी विकसित हो रही है। खेती-किसानी को बचाने की लड़ाई प्रकृति को बचाने की लड़ाई है। जिसमें किसान और गैर किसान को एकजुट होना होता है। बीसवीं सदी की वैचारिक जकड़न से मुक्त होकर किसान स्वराज के नए विचार की ओर बढ़ रहे है।

यह परिवर्तन इन आन्दोलनों की माँग में भी दिखाई देता है। पहली नज़र में कर्जमुक्ति और फसलों के पूरे दाम की मांग में कुछ भी नया नहीं लगेगा। लेकिन आज इन पुरानी मांगों को नए तरीके से निरूपित किया जा रहा है। फसल के पूरे दाम का मतलब अब केवल सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य

में बढ़ोत्तरी नहीं है। किसान आंदोलनों ने सीख लिया है, कि यह माँग बहुत सीमित है। और इसका फायदा दस प्रतिशत किसानों को भी नहीं मिलता इसलिए किसान आंदोलन अब चाहतें है, कि फसल की लागत का हिसाब बेहतर पद्धित से किया जाय इस लागत पर कम से कम पचास प्रतिशत बचत सुनिश्चित की जाय साथ ही किसानों ने यह भी समझ लिया है। कि असली मामला सिर्फ सरकारी घोषणा का नहीं है। असली चुनौती यह है, कि सरकारी समर्थन मूल्य सभी किसानों को कैसे मिल सके। इसलिए नए किसान आंदोलनों की माँग है, कि सरकारी खरीद के अलावा भी नए तरीके खोजे जाएं जिससे सभी किसानों को घोषित मूल्य हिसल हो सकें। ठीक इसी तरह कर्जमाफी की पुरानी माँग का विस्तार कर उसे कर्जमुक्ति की माँग में बदल दिया गया है। सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी/ग्रामीण बैंक के कर्ज से ही नहीं सह्कारी के कर्ज से मुक्ति की माँग भी अब जुड़ गई है। अब किसान आंदोलन याचक की तरह कर्जमाफी की प्रार्थना नहीं कर रहा आज का किसान आंदोलन देश को पिछले पचास साल से दिए अन्दान के बदले कर्ममुक्ति के अधिकार की बात कर रहा है।

छह जुलाई के मंदसौर से आरंभ हुई किसान मुक्ति यात्रा नए दौर के इस नए किसान आंदोलन की झलक दिखाती है। इसमें पिछले दो-तीन दशकों से किसानों के बीच संघर्ष करने वाले विरष्ठ किसान नेता है। तो साथ में दिलत आदिवासी संघर्ष में शामिल कार्यकर्ता भी है। पहली बार किसी राष्ट्रीय किसान समन्वय में महिला नेतृत्व की झलक और महिला आंदोलन के मुद्दों की खनक महसूस हो रही है। पहली बार किसान आंदोलन सोशल मीडिया और नई तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है।

किसान आंदोलन की विरासत को मंदसौर बारदौली और खेड़ा को याद करने वाली यह यात्रा एक ओर तो नर्मदा के विस्थापित किसानों के संघर्ष से जुड़ी वहीं दूसरी ओर यह यात्रा मेहसाणा में दलित संगठनों के आजादी कूच का हिस्सा बनी।

### किसान आंदोलनः कारण और भविष्य की दिशा

गाँव की खेती से जुड़ी अधिकांश आबादी की जिन्दगी में पिछले कुछ सालें से भयंकर संकट छाया हुआ है। जिस पर इनका आक्रोश समय पर विभिन्न रूप् से प्रकट होता रहता है। पहले यह किसानों-खेत मजदूरों की बढ़ती अत्महत्याओं के रूप में प्रकट हो रहा था। फिर यह विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक रूप् से सम्पन्न मानी जाने वाली किसान जातियों द्वारा आरक्षण की माँग के रूप में सामने आया। और अब यह महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में किसान हड़ताल के रूप् में सामने आया है। इन राज्यों में पहले तो बीजेपी-संघ ने इस आक्रोश को अपने किसान संगठन द्वारा नियन्त्रित ढंग से निर्देशित और हड़पने का प्रयास किया। आन्दोलन के बढ़ने पर इस संगठन से वार्ता और समझौते का नाटक कर आन्दोलन को वापस लेने की घोषणा भी करा ली गयी। लेकिन इससे किसान समुदाय का गुस्सा और भड़क उठा और आन्दोलन तीव्र हो गया। तब इसे पुलिस दमन से कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस की गोली से मन्दसौर में 6 आन्दोलनकारियों की मृत्यु हो गयी इसके बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा उपवास के नाटक से लेकर मृतकों को मुआवजा

न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कृषि उत्पादों की खरीद किसानों को कर्ज पर ब्याज में छूट, आदि घोषणाओं से आक्रोश को शान्त करने की कोशिश जारी है।

किसान समुदायों में इस तीव्र असन्तोष-आक्रोश का तात्कालिक कारण नोटबन्दी से पैदा नकदी के अभाव में भी किसानों ने किसी तरह उधार के सहारे जुताई, बीज, खाद की व्यवस्था कर बाजार में आयीं उनके बिक्री मूल्य में भारी कमीं हुई कुछ समय तक तो नकदी की कमी के नाम पर मण्डियों में आढ़ितयों ने फसल खरीद ने से ही मना कर दिया और गरज़बेचवा किसानों की मजबूरी में की गयी बिक्री पर मनमाने दाम दिये, जिसका भुगतान भी नोटों की कमी के नाम पर बहुत देर में किया गया या बैंक के चेक दिये गये जिन्हे खाते में जमा करने के पैसा निकालने में किसानों को भारी तकलीफ हुई इसके बाद बाजार में आयीं सरसो, तूर दाल, सोयाबीन, गेहूँ के दाम भी इसी तरह तेजी से गिरे। सरकार ने वादे के खिलाफ न्यूनतम समर्थन मूलय पर खरीदारी की व्यवस्था नहीं की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 20 लाख टन गेहूँ खरीदने की घोषणा की थी लेकिन खरीदा गया सिर्फ 2 लाख टन। महाराष्ट्र में तूर दाल की खरीदारी ही सरकार ने कुछ दिन बाद ही पूरी तरह बन्द कर दी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 30-40 प्रतिशत कम दामों पर आढ़ितयों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह भी आरोप लगा कि असल में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से दाल खरीदी ही नहीं बिल्क इन अढ़ितयों ने ही किसानों से 3-4 हजार रूपये क्विंटल पर खरीदी गयी दाल को सरकारी एजेंसियों में 5050 रूपये क्विंटल के समर्थन मूल्य पर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाया। इससे भी किसानों में तीव्र असन्तोष पैदा हुआ।

एक और तात्कालिक कारण है - मवेशियों के व्यापार पर पिछले सालों में लगायी गयी सरकारी रूकावटें और किसानो ,मवेशी, व्यापारियों पर पुलिस-प्रशासन के संरक्षण में शासक दल और संघ के गुण्डों के हमले और हत्याएँ। बड़ी संख्या में गरीब किसान और खेत मजदूर अतिरिक्त आमदनी के लिए बिक्री के लिए पशु पालते है। साथ ही अनुत्पादक पशुओं की बिक्री भी किसानों के लिए जरूरत के समय सहायक होती है। लेकिन पिछले सालों की इन घटनाओं ने पशु व्यापार को अत्यन्त सीमित कर दिया है और कीमतें बहुत नीचे आ गयी है। इसने भी किसानों-खेत मजदूरों के जीवन में मुसीबत-तकलीफ को बढ़ाया है।

छोटे किसान आमतौर पर कर्ज-उधार के सहारे उत्पादन करता है, और फसल की कटाई के समय उसे बेचकर कर्ज लौटाना उसके लिए आवश्यक होता है, नहीं तो ब्याज बढ़ जाता है। अक्सर कर्ज देने वाला ही खरीदार भी होता है। इस हालत में छोटा किसान गरज़बेचा होता है। और खरीदार की मर्जी के दामों पर बेचने को मजबूर जबिक बड़ा किसान एक ओर तो प्रशासनिक पहुँच से न्यूनतम समर्थम मूलय का लाभ उठा पाने की स्थिति में भी होता है। दूसरे वह बाजार कीमतों का फायदा उठा पाने के लिए ठहरने की स्थिति में भी होता है। अक्सर खुद ही छोटा व्यापारी भी होता है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है , कि दो हेक्टेयर तक की खेती कर रहे किसान के पास बाजा़र में बेचने वाला अधिशेष उत्पाद इतना होता ही नहीं कि लाभकारी मूल्य मिल जाने पर भी उसे जीवननिर्वाह योग्य आमदनी हो सके। इसके विपरीत उसे बाजार से उद्योग ही नहीं कृषि के भी बहुत सारे उत्पाद भोजन के लिए खरीदने होते है। जिनकी बढ़ती कीमत उसे और संकट में डाल देती है। इसलिए कृषि उत्पादों सहित बाजार में किसी भी प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की कीमतें बढ़ाने की बात इन छोटे और सीमान्त किसानों का आर्थिक संकट कम करने के बजाय उसे बढ़ाती है। साथ ही इन्हें अपने ही जैसे मेहनतकश खेत मजदूरों और शहरी मजदूरों और निम्न मध्य वर्ग के भी खिलाफ खड़ा करती है। जो मंहगाई के इस हमले के सबसे बड़े शिकार होते है।

लाभकारी मूल्यों के दौर में भी अधिकांश किसान घाटे में थे और उनकी आमदनी कम हो रही थी जो बढ़ते कर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड आदि इसी समय शुरू किये गये थे जिनमें उदारता से लिमिट बढ़ाई गयी।) के पीछे कुछ समय तक छिपी हुई थी। लेकिन यह कर्ज कभी तो वापस करना ही था जिसमें किसान अब अपने आप को असमर्थ पा रहे है। और भयंकर निराशा-हताशा के शिकार है।

अबीज/खाद आदि की अधिक लागत, कम जोत में ट्रेक्टर आदि यन्त्र खरीदने या किराये पर लेने में पड़ने वाली ज्यादा लागत, साह्कारों-आढ़ितयों से सूद पर ली गयी पूँजी, सरकारी तन्त्र का धनी किसानों के साथ खड़े होने आदि के बहुत सारे कारणों से इनके लिए खेती घाटे का सौदा है।

किसानों और खेत मजदूरों दोनों के लिए पहले ही मुख्य सवाल वैकल्पिक रोजगार और जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी बन चुका है। उनके लिए असली सवाल समर्थन मूल्य का नहीं, बल्कि जीवन निर्वाह योग्य रोज़गार प्राप्त करना है। इसलिए लाभकारी मूल्य की यह सारी लड़ाई मुख्यतः बादल पवार, शिवराज चौहान, रमन सिंह, सिन्धिया, वाड्रा, जाखड़ जैसे फार्मरों की लड़ाई हैं। यहाँ लाभकारी मूल्य का सवाल हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। उसके लिए पहले निजी मालिकाने पर अधारित पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़कर सामूहिक मालिकाने पर आधारित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ेगी।

मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन - कर्ज माफी और फसलों के गिरते हुए दामों को लेकर पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहें है। कहीं किसान उचित कीमत न मिलने के विरोध में फसलों को सड़कों पर फेंक रहें है। तो कहीं हजारों लीटर दूध को सड़कों पर बहाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के बालगुढ़ा गांव के छोटे किसान मनीष भानज ने अपनी टमाटर की 1000 पेटियां सड़कों पर फेंक दी। उनका कहना है, कि 25 किलों की एक पेटी थोक बाजार में 60 रूपये में बिक रही है। फसलों के इतने कम दाम कभी नहीं मिले और किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई किसानों ने शहरों को सब्जियों और फलों की सप्लाई करनी बंद कर दी है। बतौर कुलबीर, कम कीमत मिलने की वजह से उनके लिए अपना रोजमर्रा का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है।

### आंदोलन का राजनीतिक दबाव

अब तक शांत चल रहें आंदोलन को किसान संगठनों ने तेज करने की तैयारी कर ली है। केन्द्र शासित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी की 8 राज्यों में सरकारें है। और यहां के हजारों किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया था। किसानों की मांग थी , कि कर्ज माफ किए जाएं और तेल, अनाज और दूध के सही दाम उन्हें दिए जाएं।

राष्ट्रीय किसान महासंघ के वरिष्ठ सदस्य संदीप पाटिल का कहना है। सरकार की गलत नीतियों का ही यह नतीजा है। कि आज किसानों को जीवनयापन करना भी मुश्किल हो गया है। पिछले समय मंदसौर में मारे गए 6 किसानों के लिए हमारे मन में सम्मान है। और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो कई शहरों को जाम कर दिया जाएगा।

### आंदोलन या पब्लिसिटी स्टंट

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसान आंदोलन को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने किसानों द्वारा सड़कों पर फसलों को फेंके जाने को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया और कहा कि इन आंदोलनों को बड़े किसान संगठनों का समर्थन हासिल नहीं है।

वहीं, विपक्षी दल कांग्रस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों मंदसौर में मारे गए किसानों के पीड़ित परिवार से मुलाकार कर मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरूआत की किसानों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के साथ धोखा किया है। वह यह वादा कर सत्ता में आए थे कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिलेगा लेकिन उद्योगपति और अपने कारोबारी मित्रों को खुश रखना ही उनकी प्राथमिकता है।

# किसान संगठनों की बड़ी भूमिका

दरअसल 2014 में सत्ता हासिल करने से पहले नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह सरकार बनाने के बाद किसानों की आय दोगुनी कर देंगे यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों कि किसानों में फसलों के गिरते हुए दामों को लेकर रोष बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम रिकाॅईस ब्यूरों के डाटा के मुताबिक 1995 से अब तक कर्ज में दबे करीब 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके है। विशेषज्ञों की मानें तो भारत की कृषि व्यवस्था का तब तक समाधन नहीं निकलेगा जब तक लंबी अविध की नीति न बनाई जाए और देश के हर कोने के किसान को इसका फायदा मिले।

भारत की 130 करोड़ की आबादी का दो-तिहाई हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर करता है। हालांकि जीडीपी में इसका महज 17 फीसदी योगदान है। शहरों की तरफ तेजी से जा रही आबादी के बावजूद ग्रामीण इलाकों में आधी से अधिक आबादी रहती है। जो आगामी चुनावों में तय करेगी कि सत्ता की चाबी किसे सौपी जाए किसान संगठनों का उग्र होना चुनावों की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

#### विषय का चयन

प्रस्तुत शोधपत्र में किसानों की स्थित को दृष्टिगत रखते हुये किसानों में व्याप्त असंतोष के कारणों को जानने के प्रयास के साथ-साथ व्याप्त असंतोष के वहज से सरकार की वादाखिलाफी परिणामस्वरूप किसानों का अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जिसे सामान्यतः आंदोलन का नाम दिया जाता है। अतः किसान आंदोलनों के कारण आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तथा राजनीतिक संस्थाओं द्वारा इन आंदोलनों को रोकने एवं निराकरण हेतु जो भी उपाय किये जा रहें है। क्या वे स्थायी है। अथवा अस्थायी। यदि अस्थायी है। तो उन्हें स्थायी उपाय में बदलने के लिये क्या-क्या सुधार किये जा सकते है। तथा इसमें म. प्र. सरकार का क्या उत्तरदायित्व बनता है। किसानों की आर्थिक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा को सुधारने मे यही उत्तरदायित्व एवं सरकार का किसानों के प्रति उदारतापूर्ण रवैया ही आगे किसान आंदोलनों की दिशा तय करेगा क्योंकि यदि यह दिशा बदलेगी तभी किसानों की दशा बदलेगी।

इसी पृष्ठभूमि में यह अध्ययन म. प्र. में किसानों की स्थिति एवं किसान आंदोलन प्रशासनिक एवं राजनैतिक उत्तरदायित्व पर केन्द्रित किया गया है।

### उद्देश्य

म. प्र. कृषकों की स्थिति एवं किसान आंदोलन किसानों के प्रति राजनैतिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व का उद्देश्य यह है, कि -

- 1. म. प्र. में कृषि की स्थिति का अध्ययन करना।
- 2. म. प्र. में हुए किसान आंदोलन की पृष्ठभूति का अध्ययन करना।
- 3. किसान आंदोलन के दौरान हुए आंदोलन के राजनीतिकरण का अध्ययन करना।
- 4. किसान आंदोलन के सामाजिक राजनैतिक प्रभाव का अध्ययन करना।
- 5. किसान आंदोलन के औचित्य व अनौचित्य का अध्ययन करनां

### शोध प्रश्न अथवा अवधारणा

- 1. म. प्र. में किसानों की वर्तमान स्थिति कैसी है ?
- किसान आंदोलन होने के क्या कारण है। एवं इनकी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है ?
- 3. किसान आंदोलनों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एवं राजनीति का किसान आंदोलनों के प्रति क्या उत्तरदायित्व बनता है ?
- 4. किसानों के प्रति प्रशासनिक रवैया कैसा होना चहिये ?

### उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

- (1) जादव दिनेश गौतम ने अपने शोध ग्रथ उत्तरप्रदेश में किसान आंदोलन के प्रभाव "2013 के माध्यम से बताया है कि" होमरूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशन के परिणाम स्वरूप फरवरी 1918 में उत्तरप्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया 1919 में उत्तरप्रदेश में यह आंदोलन खुलकर सामने आया उत्तरप्रदेश के कई जिलों में लगान में वृद्धी व उपज के रूप् में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एक आंदोलन चलाया।
- (2) खहर रवीन्द्र ने आपने शोध ग्रन्थ "केरल के मालाबार क्षेत्र" में मोपल किसान आंदोलन एक अध्ययन (2009) में रविन्द्र खहर ने बताया है। कि प्रारंभ में मोपला किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ था गांधी शौकत अली, मौलाना जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को था इस किसान आंदोलन ने जल्द ही उग्र साम्प्रदायिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया।
- (3) कौर, गुरमीत ने अपने शोध बिजौलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक और माणिक्य लाल वर्मा की भूमिका और वर्तमार प्रासंगिकता (2008) में बताया है। कि यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हुकूमत की जड़ों को हिला के रख दिया यह किसान आंदोलन संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध रहा, किसानों ने लाग-बाग, लाटा, बाटा तलवार बधाई जैसी कर व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया जिसे पथिक और माणिक्य लाल वर्मा ने स्चारू रूप से आगे बढ़ाया।
- (4) पांडे सुदेशपाल ने अपने ग्रंथ भारत में किसान आंदोलन और आंदोलन का राजनीतिकरण (2018) के माध्यम से बताया है। कि वर्ष 2017 में देश में छोटे बड़े सैकड़ो आंदोलन हुए, सरकार को कृषि क्षेत्र में बोलने को मजबूर किया जिसमें महाराष्ट्र का जून 2017 देना बंद हो या नासिक से मुबंई तक का मार्च हो राजस्थान में पानी व बिजली के बवालों पर अंदोलन या तमिलराडू के किसानों का संसद मार्ग पर धरना मुख्य रहा।
- (5) यादव योगेन्द्र ने अपने आर्टिकल किसानों की मांग। (2018) के द्वारा सरकार पर पूर्ण रूप् से कटाक्ष करते हुए लिखा है। कि सत्ता में आने से पहले सरकार किसानों से वादा करती है। प्रलोभन देती है। जैसे ही सत्त हाथ में आई वादे भूल जाती हे। परिणामस्वरूप किसानों को सरकार पर उतरना पड़ता है। पिछले महिने म. प्र. में हुए उग्र किसान आंदोलन उसी वादाखिलाफी और असंतोष का परिणाम रही है।

अध्ययन क्षेत्र - मेरे द्वारा प्रस्तावित अध्ययन में मध्यप्रदेश के तीन जिले-भोपाल, उज्जैन, नरसिंघपुर चयनित किये है। जो मेरी नजर में आंदोलन के प्रमुख केन्द्र भी रहे है।

### शोध के संभावित परिणाम

- 1. किसानों की वर्तमान स्थिति में क्या अपेक्षित सुधार आया ?
- वर्तमान सरकार (राज्य केन्द्र) ने किसानों को वादानुरूप अपनी योजनाओं के माध्यम से संतुष्ट किया या नहीं ?
- 3. किसानों की आय में वृद्धि संबंधित
- मध्यप्रदेश के किसान और देश के विभिन्न राज्यों के किसानों के आर्थिक सामाजिक स्तर का त्लनात्मक अध्ययन
- 5. पिछले पाँच सालों में किसानों की स्थिति में आये परिवर्तन विभिन्न स्तरों से संबंधित।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1. कौर गुरूपीत (2008) बिजौलिया किसान आंदोलन वर्तमान प्रासंगिकता गुरूनानक देव प्रकाशन मोहाली (संयुक्त प्रकाशन) ISBN 09883310 पृष्ठ 31 PB
- 2. खहर रवीन्द्र (2009) केरल के मालावार क्षेत्र में मोवला किसान आंदोलन का प्रतिरूप "आरूषि प्रकाशन काच्चि केरला भाग- IV पृष्ठ 17,18 कोच्चि"
- 3. जाधव दिनेश गौतम (2018) उत्तरप्रदेश में किसान आंदोलन का प्रभाव एवं जनभागीदारी-एक अध्ययन आगरा विश्वविद्यालय शोध ग्रंथ पृ. 137-159उत्तरप्रदेश
- 4. पांडे सुदेश पाल (2018) "भारत में किसान आंदोलन व राजनीतिक भागीदारी" लक्ष्मी बुक पब्लिकेशन शोलापुर (महाराष्ट्र) पृष्ठ सं. 179-180 VOL. 3
- 5. यादव योगेन्द्र (2018) "िकसानों की मांग- औचित्यता" न्यू टाइम्स जर्नल्स मासिक पत्रिका ग्रेटर नोयडा पृष्ठ-11 उत्तरप्रदेश
- 6. सी. आर. कोठारी (2012) शोध प्रविधि "न्यू एन इंटरनेशनल पब्लिकेशन" न्यू दिल्ली।

### समाचार पत्र

- 1. दैनिक ट्रिब्यून जून 13,2017 म. प्र. भोपाल
- 2. दैनिक भास्कर जून 2017 म. प्र.
- 3. दैनिक बालाघाट म. प्र.
- 4. नवभारत टाइम्स जून 2017 न्यू देहली
- हिन्द्स्तान अगस्त म. प्र.